

पशुपालन को समर्थन देने वाली सरकारी योजनाएँ



**मनोज जाट^{1*}, सुनीता
कुमारी गुर्जर², संजय
यादव³**

^{1,2,3}पशु उत्पादन निभाग,
राजस्थान कृषि महाविद्यालय,
महाराणा प्रताप कृषि एवं
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
राजस्थान – 313001

पशुपालन भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो खाद्य सुरक्षा, रोजगार और ग्रामीण आय में आकर्षक योगदान करता है। पशुपालन और डेयरी विभाग के अनुसार, पशुधन क्षेत्र कुल जीडीपी का लगभग 4.5% और कृषि जीडीपी का 25% से अधिक योगदान करता है। इसकी संभावनाओं को देखते हुए, भारत सरकार ने पशुपालन को समर्थन करने और आधुनिक बनाने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। ये पहलें पशुधन उत्पादकता को बढ़ावा देने, पशु चिकित्सा देखभाल को सुधारने, डेयरी और पोल्ट्री विकास को समर्थन देने और किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से डिज़ाइन की गई हैं।

1.राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM), जो कि 2014 में शुरू किया गया, भारत की देशी गायों की नस्लों को वैज्ञानिक और पारस्परिक तरीके से संरक्षित और विकसित करने के लिए काम करता है। यह मिशन देशी नस्लों के जैसे गिर, साहीवाल और राठी की आनुवंशिक सुधार को बढ़ावा देता है। इसमें गोकुल

ग्राम—एकीकृत देशी गाय केंद्रों—की स्थापना शामिल है, जहाँ प्रजनन और संरक्षण कार्य किए जाते हैं। यह योजना आईवीएफ और एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसी आधुनिक प्रजनन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, यह देशी गायों के साथ काम करने वाले उत्कृष्ट किसान

और संस्थाओं को सम्मानित और पुरस्कृत करती है। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय गोकुल मिशन ने दूध उत्पादकता में महत्वपूर्ण वृद्धि की है और भारत की मूल्यवान पशुधन जैव विविधता को संरक्षित रखने में मदद की है।



2. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM), जो 2014 में शुरू किया गया था और फिर से 2021 में, का लक्ष्य पशुधन क्षेत्र की स्थायी और समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से छोटे मवेशियों जैसे भेड़, बकरियां और पोल्टी पर फोकस करना। इस मिशन को कई उप-मिशनों में विभाजित किया गया है, जिनमें घुड़सवार पशु आहार और चारा विकास, पशुधन विकास, कौशल विकास और क्षमता निर्माण, और जोखिम प्रबंधन और बीमा शामिल हैं। यह योजना पोल्टी, सूअर पालन, और छोटे मवेशी व्यवसायों में आदिवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, यह किसानों के तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करती है और चारा उगाने और संरक्षण के लिए प्रोत्साहन करती है। इन हस्तक्षेपों के द्वारा, NLM चारा और आहार की कमी को कम करने, चारा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और आत्म-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पशुधन आधारित उद्यमिता के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। यह मिशन ग्रामीण आजीविका में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि और भारत में पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है।

3. पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष (AHIDF)

लॉन्च किया गया: 2020

यह केंद्रीय सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के निवेश को पशुधन मूल्य श्रृंखला में बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत दूध प्रसंस्करण इकाइयों, मांस प्रसंस्करण संयंत्रों, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और पशु आहार

निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पूंजी तक पहुंच को सरल बनाने के लिए योजना में ब्याज अनुदान और ऋण पर क्रेडिट गारंटी समर्थन भी शामिल है। यह योजना किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), निजी खिलाड़ियों और डेयरी सहकारी संस्थाओं को सतहती करती है। AHIDF डेयरी और मांस उत्पादों में मूल्य वर्धन, प्रसंस्करण और निर्यात क्षमता को आगे बढ़ाता है, साथ ही रोजगार अवसरों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण में समर्थन प्रदान करता है। यह कोष पशुपालन को आधुनिक बनाने और भारत में आत्मनिर्भर पशुधन क्षेत्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है।

4. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना (LHDC)

उद्देश्य: प्रभावी रोग नियंत्रण के माध्यम से स्वस्थ पशुधन सुनिश्चित करना।

मुख्य गतिविधियाँ:

- देशव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम।
- फुट एंड माउथ डिजीज (FMD) और ब्रुसेल्लोसिस के खिलाफ सामूहिक टीकाकरण।
- पशु चिकित्सालयों और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना।

प्रभाव:

- पशुओं का स्वास्थ्य सुधरना।
- संक्रामक रोगों के कारण मृत्यु दर और बीमारी में कमी।

5. डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS)

यह सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के बीच डेयरी क्षेत्र में आत्म-रोजगार को बढ़ावा देना है। योजना के तहत छोटे डेयरी फार्मों की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज और चिलिंग संरचनाओं, वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस इकाइयों की स्थापना और आधुनिक डेयरी उपकरण जैसे दूध निकालने की मशीनें और बुल्क मिल्क कूलर की खरीद का समर्थन किया जाता है। यह योजना विभिन्न लाभार्थी श्रेणियों के लिए 25% से 33% तक की पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है, जिसमें SC/ST और महिलाएँ भी शामिल हैं। DEDS ने दूध उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है, प्रसंस्करण और भंडारण क्षमता में सुधार किया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। वित्तीय और बुनियादी ढांचा समर्थन प्रदान करने के माध्यम से, यह योजना डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने और छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

6. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

लॉन्च किया गया: 2020

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए है, लेकिन एकीकृत खेती प्रणालियों को बढ़ावा देकर अप्रत्यक्ष रूप से पशुपालन को समर्थन देती है। यह योजना एकाकल्चर विकास, कोल्ड चैन और विपणन बुनियादी ढांचे के निर्माण, और क्षमता निर्माण और शोध को सशक्त करने पर जोर देती है। मछली पालन को पोल्टी और डेयरी जैसे पशुधन गतिविधियों के साथ एकीकृत

करने से, PMMSY किसानों को उनके आय स्रोतों में विविधता लाने में सहायता प्रदान करती है और भूमि और जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करती है। इस योजना ने ग्रामीण आय में वृद्धि, पोषण सुरक्षा में सुधार और सतत कृषि प्रथाओं के माध्यम से संसाधन प्रबंधन में योगदान दिया है। PMMSY आत्मनिर्भर, लचीली और समावेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएँ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

7. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) for animal husbandry farmers

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पशुपालन किसानों के लिए मूल KCC योजना का विस्तार है, जिसका लक्ष्य पशुपालन और डेयरी किसानों को सस्ते संस्थागत ऋण प्रदान करना है। यह योजना डेयरी, पोल्ट्री, भेड़, बकरी और यहां तक कि भूमिहीन पशुपालन किसानों को भी शामिल करती है, जिससे व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित होता है। KCC कम ब्याज दरों पर लघु अवधि के कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान करता है, जिसका उपयोग आहार, दवाइयाँ, और मूलभूत बुनियादी ढांचे की खरीदारी के लिए किया जा सकता है। इसमें मृत्यु या प्राकृतिक आपदाओं के लिए बीमा कवरेज भी दी जाती है, जो किसानों के

लिए सुरक्षा जाल प्रदान करता है। इस पहल ने समय पर ऋण तक पहुंच में महत्वपूर्ण सुधार किया है, अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता को कम किया है और पशुपालन किसानों की आर्थिक लचीलापन को मजबूत किया है, इस प्रकार ग्रामीण भारत में पशुपालन क्षेत्र के समग्र विकास को समर्थन दिया है।

8. पशु रोग नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ASCAD)

यह एक केंद्रीय सरकार का पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों को पशु रोगों के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सहायता प्रदान करना है। योजना रोग निदान प्रयोगशालाओं को सशक्त बनाने, नियमित सर्विलांस और निगरानी संचालन, और पशु चिकित्सकों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर मुख्य रूप से कड़ी निगाह रखती है। ASCAD संचारी पशु रोगों की प्रचलन में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करके, यह योजना पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को बेहतर बनाती है, जिससे उनके व्यापार और निर्यात क्षमता में वृद्धि होती है। ASCAD पशुपालन क्षेत्र को सुरक्षित रखने और भारत में सतत

पशु स्वास्थ्य प्रबंधन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

मजबूत समर्थन के बावजूद, आहार की कमी, अपर्याप्त पशु चिकित्सा सेवाएँ, कम जागरूकता, और इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी जैसी चुनौतियाँ बनी रहती हैं। आगे बढ़ते हुए, यह आवश्यक है कि:

- पशु चिकित्सा सेवाओं की अंतिम स्तर तक पहुंच में सुधार किया जाए।
- जलवायु-लचीला पशुपालन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाए।
- योजना का समन्वय जमीनी स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।
- योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन को मजबूत किया जाए।

निष्कर्ष

सरकारी योजनाएँ पशुपालन को समर्थन प्रदान करती हैं, जिन्होंने ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने, खाद्य और पोषण सुरक्षा का सुनिश्चित किया, और महिलाओं एवं छोटे किसानों को शक्ति प्रदान की। अनन्त निवेश, प्रौद्योगिकी एकीकरण, और नीति समर्थन भारत में एक सक्रिय और लचीले पशुपालन क्षेत्र को सुनिश्चित करेंगे।